ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 15, Issue 1,Jan 2025 Impact Factor 8.059 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

बैकिंग व्यवस्था में वित्तीय समावेशन व वित्तीय साक्षरता चुनौती का अध्ययन

जगदीश राय (शोधार्थी)[1], डॉ. अमन गुप्ता (सहायक प्रोफेसर)[2]

वाणिज्य विभाग,
श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टिबरेवाला विश्वविद्यालय

झुंझनू, राजस्थान
[1]raijagdishrai@gmail.com

वाणिज्य विभाग,

श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टिबरेवाला विश्वविद्यालय,

झुंझनू , राजस्थान
2amangupta76@gmail.com

सारांश-

स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक देश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास की अनिवार्यता पर बल दिया जाता रहा है। ग्रामीण विकास हेतु सरकार एवं नीति-निर्माताओं द्वारा निरन्तर प्रयास किये जाते रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए समय-समय पर योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न नीतियाँ एवं कार्यक्रम प्रारंभ किए गये। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1951 से अब तक तेरह पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा चुका है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरूआत से ही ग्रामीणों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विकास योजनायें चलायी गयी। जिससे इनका सामाजिक व आर्थिक विकास हो सके। क्योकि देश की आधी से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रो में रहती है जिनका सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। परन्तु, ग्रामीण व्यक्ति एवं समाज के नीचले से नीचले स्तर पर बैठ व्यक्ति तक विकास एवं वित्तीय सेवाएं पहुंच पायी है? यह एक विचारणीय प्रश्न है जो बुद्धिजीवियों के मन मस्तिष्क में उत्पन्न होता है।

राजस्थान राज्य भारत के पिछडे राज्यों में आता है जहां अकाल व सुखे जैसी समस्याएँ विकराल रुप में आती है। राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले की सामाजिक व आर्थिक स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। यदि राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की स्थिति तुलना करें तो यह जिला पिछडा हुआ है। प्रदेश में हनुमानगढ़ जिले की महिलाओं की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। विशेष तौर से अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है। इन महिलाओं पर वित्तीय समावेशन के कार्यक्रमों का प्रभाव कम प्रतीत होता है ये महिलायें शैक्षिक रूप से कमजोर होने के कारण ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी

नहीं है।

शब्द संकेत - वित्तीय समावेशन, बैकिंग व्यवस्था, वित्तीय साक्षरता।

वित्तीय समावेशन व वित्तीय साक्षरता –

वित्तीय समावेशन से सामान्य आशय समाज के हर वर्ग के व्यक्ति विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों तक उपयुक्त वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई नीति से है। हांलाकी वित्तीय समावेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एच.आर.खान समिति ने किया था लेकिन यह कोई नवीन प्रक्रिया की शुरूआत आजादी के उपरांत ही शुरू हो गई थी। 2008 में रंगराजन समिति के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने गति प्राप्त की।वित्तीय समावेशन हेतु विश्व बैंक, सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाये, विशेषकर फ्री बैंक खाते खोलना, खाते में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नही, इलैक्ट्रानिक भुगतान चैनल द्वारा बैंक में जमा एवं निकासी, कही भी बैंकिंग और कभी भी बैंकिंग की अवधारणा, क्रेडिट कार्ड सुविधा, लोन सुविधा, एटीएम सुविधा तथा एटीएम पर जमा एवं निकासी की सुविधा उपलब्ध कराना प्रमुख है।

वित्तीय समावेशन का अभाव समाज एवं व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होता है। जहाँ तक व्यक्ति का सबंध है, वित्तीय समावेशन के अभाव में, बैंकिंग सुविधा से वंचित लोग अनौपचारिक बैकिग क्षेत्र से जुड़ने के लिए बाध्य हो जाते है, जहाँ ब्याज दरें अधिक होती है और प्राप्त होने वाली राशि काफी कम होती है। चूंकि अनौपचारिक बैकिंग ढांचा कानून की परिधि से बाहर है, अतः उधार देने वालो और उधार लेने वालों के बीच उत्पन्न किसी भी विवाद का कानूनन निपटान नहीं किया जा सकता। अतः कहा जा सकता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को संस्थागत बैकिंग व्यवस्था अर्थत बैंकों के माध्यम से धन की लेन - देन की प्रक्रिया से जोड़ना वित्तीय समावेशन अथवा कहलाता है, यह न केवल लोगों के समृद्धि के लिए आवश्यक होता है बल्कि यह किसी राष्ट्र की समृद्धि को निर्धारित करता हैं वित्तीय समावेशन से व्यक्ति, परिवार एवं समाज सुरक्षित होता है। वह किसी भी तरह के आकस्मिक आर्थिक संकट से निपटने में सक्षम हो पाता है। इसके साथ अपने धन का कुशल निवेश कर वह अधिकाधिक लाभ प्राप्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बचत, निवेश, ऋण और व्यय के बारे में शिक्षाप्रद जानकारी, ज्ञान और कौशल हासिल करना व्यक्तिगत वित्त को प्रबन्धित करने के लिये आवश्यक ज्ञान को वित्तीय साक्षरता कहते हैं। कदापि इसका

अर्थ यह नहीं है कि इसके लिये वित्त के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान की जाये, बल्कि यह तो ऋण को उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से समझने, मुद्रा को प्रबन्धित करने वित्तीय जोखिमों को न्यूनतम करने तथा बचतों से दीर्घकालीन लाभ प्राप्त करने जैसे विविध पहलुओं को समाहित करती है। दूसरी ओर वित्तीय शिक्षा को व्यापक रूप से वित्तीय बाजार उत्पादों, विशेष कर सुसूचित चयन करने के लिये प्रतिफल तथाजोखिमों की जानकारी रखने एवं समझने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से वित्तीय साक्षरता प्राथमिक रूप से व्यक्तिगत वित्तीय शिक्षा से सम्बद्व है, ताकि व्यक्ति अपने कल्याण में सुधार लाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने योग्य हो जाये और वित्तीय मामलों के कष्टों से बच सके।

ग्रामीण शिष्टाचार अब भौतिकवादी हो गया है। समर्पित शिक्षक, प्रबुध्द एवं उत्तरदायी बुजुर्ग लगभग बुझ चुके हैं। भौतिक उत्थान के साथ-साथ जीवन मूल्य भी परवर्तित हो रहे हैं। वैकल्पिक रूप से कुछ निर्धारित मानदण्डों के चारों ओर की वस्तुओं के विस्तृत प्रयोग से ऐसा हो रहा है। बढ़ते शिक्षा स्तर तथा कृषि क्षेत्र से बाहर रोजगार के अवसरों के कारण गावों में संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हो रहा है। गांव के गरीब लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग होने से गांव के स्थानीय वोहरों से पीड़ियों पुराने सम्बन्धों को तोड़ रहे हैं। परम्परागत सम्बन्धों को तोड़कर स्वामी-सेवक सम्बन्ध भी बदल गये हैं। रोजगार की तलाश करने हेतु गाँवों के बाहर रहने के कारण गांव के आदमी की शहर की ओर प्रवास करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उनका सोचना है कि उनकी पसन्द मनोरंजनात्मक सुविधाओं के कारण एक कस्बा अथवा शहर उनके रहने के लिये एक सुखी स्थान है।

यदि देश की समस्त आबादी को विभिन्न वित्तीय गतिविधियों तथा विकासपरक कार्यक्रमों से जोड़ना है तो वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में हमें दृढ़ निश्चय के साथ काम करना होगा। इस दिशा में कार्य करने के लिए बैंकों को सबसे पहले उन कारणों को दूर करना होगा जिनकी वजह से कमजोर, उपेक्षित, वंचित एवं कम आय वर्ग के लोगों तक बैंकिंग सुविधाएँ नहीं पहुँच पायी है। हालांकि इन सभी के पीछे हमारे देश की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियां भी जिम्मेवार है।

वित्तीय समावेशन के उद्देश्य –

वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य उन प्रतिबंधों को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से लोगों को बाहर रखते है और किसी प्रकार के भेदभाव के बिना उनकी विशिष्ट आवश्यताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवाओं विशेषकर लेनदेन, भुगतान, बचतें, ऋण, बीमा आदि यथोचित मूल्य एवं पारदर्शी

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 15, Issue 1,Jan 2025 Impact Factor 8.059 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

तरीकों से उपलब्ध कराना है। वित्तीय समावेशन बैंकिंग जागरूकता से जुड़ा विषय है जिसका उद्देश्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को आर्थिक विकास के लाभों से सम्बद्ध करना है और इसकी शुरूआत बैंक खाते खुलवाने से होती है। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक को अर्थव्यवस्था के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने एवं आर्थिक सुधारों से कोई व्यक्ति वंछित न रहे ऐसे उद्देश्य को वित्तीय समावेशन में सम्मिलित किया गया। वित्तीय समावेशन के निम्न उद्देश्य है-

- आम जनता को बैंकिग व्यवस्था से जोड़ना जिससे जमा करने की प्रवृत्ति को जन्म दिया जा सके। जब देश में जमा धनराशि का अनुपात बढता है तब ऐसे में बैंकिग व्यवस्था में तरलता बढ़ती है जिससे ऋण का प्रभाव बढ़ता है जो उपभोग एवं निवेश सुनिश्चित करता है।
- आम जनता को ऋण की प्राप्ति सुनिश्चित कराना, जिससे साहूकारों पर निर्भरता को कम कर ऋणी को शोषण से बचाया जा सके।
- आम जनता को किसी भी प्रकार के लाभ अथवा परिदान एवं बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी तक प्रत्यक्ष रूप से पहुचाया जा सके।

वित्तीय समावेशन का प्रसार –

वित्तीय समावेशन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय साक्षरता का समुचित प्रसार हो और वित्तीय समावेशन के वाहक बीसी - बीएफ में ऐसे व्यक्तियों को रखा जाए जिन्हें ग्रामीण जनता और बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों की आर्थिक जरुरतों व ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समुचित जानकारी हो। तभी, वह वित्तीय समावेशन के मूल उद्देश्यों को वंचित आबादी तक क्रियान्वित कर सकता है। निम्नलिखित बिंदूओं से हम वित्तीय साक्षरता के प्रसार में बीसी - बीएफ की भूमिका का आकलन कर सकते है –

- वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में:- वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को वित्तीय साक्षरता व जागरुकता से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बीसी - बीएफ बैंक व ग्राहक के बीच संपर्क साधन बनकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भरपूर सहायता कर सकते है।
- आर्थिक रुप से सशक्त बनाकर:- बीसी - बीएफ वित्तीय साक्षरता द्वारा गरीबों को बचत योजनाओं, विभिन्न बैंकिंग सेवाएं,उत्पादों का बाजार में विपणन इत्यादि के बारे में जानकारी देकर उन्हें स्वावलंबी बना सकते है।

- कम वित्तीय साक्षरता से आर्थिक विकास में रुकावट:- वित्तीय साक्षरता गरीब लोगों को अपने परिवार, गाँव व शहर के विकास हेतु सशक्त बनाने का सबसे उपयुक्त साधन है। बीसी - बीएफ ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन व उसे प्राप्त करने के स्रोत, बैंक ऋण सुविधा, सब्सिडी, पूंजी इत्यादि की जानकारी प्रदान कर देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकते है।
- ग्राहक प्रसार:- बैंक विविध तरीकों द्वारा अपना व्यवसाय बढा़ ना चाहते है लेकिन यह तभी संभव होगा, जब बैंकिंग और ग्राहक के बीच वित्तीय संवाद स्थापित होगा। इस कार्य में बीसी - बीएफ महत्वपूर्ण सहयोग कर सकते है।

वित्तीय साक्षरता के उद्देश्य-

वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करना वित्तीय साक्षरता का प्रमुख उद्देश्य है। इसी के साथ कुछ अन्य उद्देश्य बताए जा सकते है-

- वित्तीय रुप से वंचित लोगों को वित्तीय रुप से साक्षर करना।
- मात्र धन व्यवहार को ही प्राधान्य न देते हुए धन प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- अपनी आवश्यकताओं तथा उपलब्ध सेवा/उत्पादों का योग्य उपयोग करना।
- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सेवाओं तथा उत्पादों के प्रति शिक्षित करना।
- ऋण प्राप्त करने हेतू तथा उसके योग्य उपयोग के लिए वित्तीय परामर्श देना।

वित्तीय साक्षरता के मार्ग में व्याप्त समस्याएँ-

वित्तीय साक्षरता का मुख्य उद्देश्य वित्तीय रुप से वंचित लोगों को वित्तीय साक्षर करना रहा है। इस मार्ग में अनेक समस्याएँ है जिसे निम्नरुपसे स्पष्ट किया जा सकता है –

- योग्य योजनाओं तथा राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव।
- लोगों में निरक्षरता या बहुत ही कम पढ़ा-लिखा होना।
- संपूर्ण देश के लिए समान शिक्षा नीति का अभाव।
- सक्षम रोजगार योजनाओं का अभाव।
- बैंकिंग सेवाओं का ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में विस्तार न किया जाना।
- क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा हिन्दी का समुचित उपयोग न किया जाना।

- सूचना प्रौद्योगिकी की सरल प्रणाली का उपयोग न किया जाना।

वित्तीय साक्षरता की सफलता के लिए आवश्यक प्रयास –

वित्तीय साक्षरता को सफल बनाना वित्तीय समावेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए कुछ निम्नलिखित प्रयास करना जरुरी हो जाता है -

- सरकार द्वारा वित्तीय साक्षरता के प्रचार हेतू जनमानस में जागरुकता लाने के लिए शिक्षाप्रद तथा प्रोत्साहनप्रद अभियान चलाया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा देश की समस्त शिक्षा संस्थाओं में माध्यमिक स्तर से ही वित्तीय साक्षरता हेतु बुनियादी वित्तीय आवश्यकताओं पर अनिवार्य रुप से अध्ययन शुरु किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा समस्त प्रसार माध्यमों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के प्रचार-प्रसार हेतू व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए।
- जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतो, जिला परिषदों, नगर परिषदों, महानगर पालिकाओं के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के अभियान को सफल बनाने हेतु प्रयास किया जाए।
- एनजीओं,समाजसेवियों, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, सेवानिवृत्त शिक्षकों तथा कर्मचारियों आदि को वित्तीय साक्षरता के अभियान में शामिल करना।
- सरकार को डाकघरों जैसे विशाल नेटवर्क को वित्तीय साक्षरता अभियान हेतू उपयोग में लेना चाहिए।
- ऋण प्रबंधन तथा मुद्रा प्रबंधन की आवश्यकता को समझना चाहिए।
- बचत प्रबंधन को सही ढंग से समझाया जाना चाहिए।
- बैंकिंग सेवाओं के उपयोग के विषय में जागरुकता लाना।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता का प्रारंभ किया जाना।
- वित्तीय परामर्श सेवाएँ सभी स्तरो पर उपलब्ध कराना।
- लोगों को ऋण से संबंधित उत्तरदायित्वों के प्रति जागरुक बनाना।
- लोगों में बचत की आदतों का विकास करना।

वित्तीय साक्षरता की राह में आ रही अड़चनों के निवारण के उपायः-

- वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में सभी गैर बैंकिंग संस्थाओं को भागीदारी बनानें के बजाय अच्छी

संस्थाओं के चुनाव की रणनीति अपनाई जाए।

- व्यवसाय प्रतिनिधियों और व्यवसाय सहायकों का चुनाव करते समय वंचित तबकों के योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए।
- वसूली एजेंटों की बहाली की पद्धति को समाप्त किया जाए और सरकारी एजेंसियों को इस काम के लिए सक्षम बनाया जाए।
- सामाजिक बैंकिंग को बहाल करने के लिए राष्ट्रीकृत बैंकों पर से लाभप्रदता का दबाव कम किया जाए। निजी क्षेत्र के लिए भी एक निश्चित प्रतिशत से अधिक लाभ कमाना आर्थिक अपराध घोषित किया जाए। क्योंकि बहुत अधिक लाभ का मतलब उपभोक्ताओं का वित्तीय शोषण ही है।
- वित्तीय समावेशन अथवा वित्तीय साक्षरता के कार्यों की प्रगति अथवा लक्ष्यों को पूरा करने संबंधी संस्थाओं के दावों की निगरानी अथवा जाँच की प्रभावी प्रणाली विकसित की जाए।
- परामर्श देने और निगरानी अथवा जाँच करने जैसी जिमेदारीयों के लिए पूरी तरह से हितधारी संस्थाओं पर ही भरोसा न करके इन कामों के लिए स्वतत्रं एजेंसियाँ तैयार की जाएं। दोनों प्रकार की एजेंसियों द्वारा कर्ज देने जैसी सिफारिशें वित्तीय संस्थांओं के लिए बाध्यकारी होनी चाहिए।
- सभी प्रकार की जानकारियाँ, रिपोर्ट, नियमावली, प्रचार सामगी्र आदि मूल रूप से हिंदी में तैयार कराई जाए। भारतीय भाषाओं के वाक्यं विन्यारस एवं शब्दाववली में अधिक समानता होनें के कारण हिंदी में उपलब्धय सामगी्र को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करके प्रयोग करना विभिन्न भाषायी क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के लिए अधिक आसान होगा।

निष्कर्ष –

वित्तीय साक्षरता के सफलता का प्रमुख लाभ यह होगा की हमारी अर्थव्यवस्था के अंतिम व्यक्ति को इस व्यवस्था से जुड़ने का अधिकार मिलेगा, उसकी वित्तीय बुद्धिमत्ता का विकास तथा निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी, मुद्रा के लेन-देन के साथ ही उसके योग्य प्रबंधन की क्षमता प्राप्त होगी, वित्तीय तथा बैंकिंग सेवाओं की मांग का सृजन होगा, उन्हे ऋणग्रस्तता के संकट से बाहर आने हेतू अभिप्रेरणा मिलेगी, बचत करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी तथा बचत का योग्य उपयोग होगा, बैंक को भविष्य का मूल्यवान ग्राहक प्राप्त होगा।

संदर्भ

1. आंकोदिया, हेमलता , गरीबों का भविष्य संवारती सामुदायिक अल्पबचत समितियाँ, कुरुक्षेत्र, नवम्बर-09, पृ. 3, 2009
2. उदयसिंह , भीलों की कुरीतियाँ मिटाता ‘सम्पर्क’, कुरुक्षेत्र, जून, पृ. 3-7, 2009
3. बोहरा, सुनीता , लघु ऋण व्यवस्था के जरिए महिला सशक्तिकरण, कुरुक्षेत्र, नवम्बर, पृ. 20-23 , 2009
4. भारतीय रिजर्व बैंक: वर्किंग पेपर सीरीज (डीईपीआर): 8/2011), भारतीय रिजर्व बैंक प्रकाशन
5. राकेश मोहन: इकोनॉमिक ग्रोथ, फायनांशियल डीपेनिंग ऐंड फायनांशियल इन्क्लूजन
6. शर्मा, रमाकातं: वित्तीय समावेशन ,मेधा बुक्स, एक्स 1, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32, सितबंर 2008
7. पी. कुमार, रूपम मिश्र, पुष्प कुमार शर्मा (सं.): वित्तीय समावेशन के विविध आयाम, आधार प्रकाशन प्रा. लिमिटेड, एससीएफ 267, सेक्टर 16, पंचकूला, हरियाणा - 134113, 2009
8. कमला राजन, विवेक मैंदर्गी (सं.): वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता, (कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे), मेधा बुक्स, एक्स 1, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32, सितबं र 2011
9. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधि रिपोर्ट - 2009-10”- भारतीय रिजर्व बैंक – पृष्ठ संख्या 33,34